जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 14 संख्याः 351 प्रभात हिण्डौन सिटी, शुक्रवार 21 अक्टूबर, 2022 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

मुलायम सिंह की पुरानी सीट मैनपुरी के लिये भारी व्यूह रचना तैयार की भाजपा ने

सपा के गढ़ रामपुर व आजमगढ़ पर कब्जा करने के बाद, मैनपुरी की जीत से 2024 के चुनाव के माहौल व मनोबल पर क्या असर होगा, भाजपा इससे पूरी तरह वाकिफ है

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। भाजपा में इस समय मैनपुरी लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी से छीनने के लिये, एक साथ कई प्रहार करने वाली रणनीति तैयार करने का काम जोरों पर है। यह सीट वरिष्ठ सपा नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण खाली हुई है।

भगवा पार्टी को जो संभावनाएं नजर आ रही हैं, उनमें यह विकल्प भी शामिल है कि देर-सवेर घोषित होने वाले इस उप चुनाव में, अखिलेश यादव से विमुख हो चुके उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की संभावित उम्मीदवारी का समर्थन किया जाये।

शिवपाल, जो पिछले महीनों में भाजपा के नजदीक नजर आये हैं, ने मुलायम सिंह के जीवनकाल में ही यह इच्छा व्यक्त की थी कि अगर उनके बड़े स्वास्थ्य कारणों से 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लेते हैं, तो वे (शिवपाल) मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे।

ऐसी संभावना है कि केन्द्र सरकार तथा उसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार भी आने वाले सप्ताहों में "पसमन्दा मुस्लिमों" के लिये कुछ कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं कर सकती है, जो मुस्लिम आबादी का 80 प्रतिशत हिस्सा बताये जाते हैं।

ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मैनपुरी उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में बड़ी संख्या में "डमी" या "प्रॉक्सी" प्रत्याशी नज़र आ सकते हैं, जिनमें से कुछ भाजपा समर्थित होंगे।

इधर मायावती की बसपा भी मुसलमानों तक अपनी पहुँच बनाने की आक्रामक योजनाएं बना रही है। ऐसी संभावना है कि बसपा मैनपुरी सीट पर किसी मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी को उतारेगी।

ज्ञातव्य है कि मुस्लिम और यादव मतदाता ही इस सीट के चुनाव-परिणाम तय करते हैं।

सपा को उसके दो गढ़ों- आज़मगढ़ और रामपुर में बुरी तरह से हरा देने में कामयाब होने के बाद, 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, भाजपा की मैनपुरी जीत पार्टी के लिये प्रतीकात्मक रूप से बहुत अधिक मूल्यवान सिद्ध होगी।

2014 तथा 2019 के संसदीय चुनावों में, मैनपुरी के भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य ने मुलायम सिंह को अच्छी टक्कर दी थी। लेकिन अगर शिवपाल भाजपा में विधिवत शामिल हो जाते हैं तो भगवा पार्टी इस बार उनके पक्ष में खड़ी हो सकती है। दूसरे विकल्प के रूप में, भाजपा शाक्य को खड़ा कर सकती है, लेकिन इसके साथ ही, वह शिवपाल की उम्मीदवारी का भी अनौपचारिक रूप से समर्थन कर सकती

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भाजपा ने मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल पर हाथ रखा है, मैनपुरी उपचुनाव के लिये।
- शिवपाल स्वयं भी मैनपुरी से चुनाव लड़ने की इच्छा दिखा चुके हैं, पर, उस समय मुलायम सिंह जीवित थे, अतः शिवपाल चाहते थे कि मुलायम सिंह वहां से अपनी उम्मीदवारी खत्म कर दें तभी वे (शिवपाल) प्रत्याशी बनें।
- मैनपुरी में मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, भाजपा, बसपा को भी प्रेरित कर रही है कि, वह मजबूत मुसलमान उम्मीदवार उतारे और शिवपाल की उम्मीदवारी को मजबूती मिले।
- शिवपाल को मूल चुनौती अखिलेश यादव की पार्टी से ही होगी, पर मुसलमान-यादव कॉम्बिनेशन कमजोर होने से मुलायम सिंह की धरोहर पर कब्जा करने का सुंदर सपना देख रही है भाजपा।

आई.बी. ने खरीदा था पैगसस?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। एक भारतीय समाचार वैवसाइट, "द वायर" में गुरुवार को प्रकाशित एक सनसनीखेज रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की घरेलू

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भारतीय न्यूज़ वैबसाइट में छपी एक सनसनीखेज रिपोर्ट में कहा गया है कि, वर्ष 2017 में लगभग 2 करोड़ रूपये में इन्टैलिजैंस ब्यूरो ने पैगसस स्पायवेयर खरीदा था।

सैन्य सेवा कर्मी और सैनिक में अंतर

जयपुर, 20 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि सैन्य सेवा में कार्यरत असैनिक कर्मचारी और सैनिक में अंतर होता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में आरक्षण के एक मामले में यह राय दी। कोर्ट ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि, सेना के असैनिक कर्मचारियों को सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है।

ब्रिटेन की प्र.मंत्री ने इस्तीफा दिया

इसे महारानी एलिजाबेथ के युग की पूर्ण समाप्ति माना जा सकता है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाये तो ग्रेट ब्रिटेन में एलिज़ाबेथ युग समाप्त हो गया है क्योंकि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस ने कल इस्तीफा दे दिया। वे ऐसी अंतिम प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें स्व. महारानी एलिज़ाबेथ ने पद की शपथ दिलाई थी।

अब, सात दशक से ज्यादा अवधि में ऐसा पहला अवसर आयेगा, जब प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति को कोई नया राष्ट्राध्यक्ष शपथ दिलायेगा।

ब्रिटिश इतिहास में, एलिजाबेथ प्रथम युग संभवतः सबसे शानदार एवं महानतम युग था, जब लिटिल इंग्लैंड" ने उस रुप में उभरना शुरु किया था, जिसे बाद में "ग्रेट ब्रिटेन" कहा गया।

एलिज़ाबेथ द्वितीय युग की समाप्ति ऐसी प्रतीत हो रही है, जैसे वह इतिहास पीछे लौट रह हो। "ग्रेट ब्रिटेन" एक बार फिर "लिटिल ब्रिटेन" बनता जा रहा है। सत्ता की महान दिखावटी तड़क-भड़क में अब पूर्व के अवशेष ही बचे हैं।

इसके बावजूद स्व. क्वीन की अंतिम प्रधानमंत्री ने देश को बदहाली में छोड़ दिया। उनके वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत एक मिनी बजट में अनफण्डेड टैक्स में कटौतियों की घोषणा के साथ ही वित्तीय बाजारों ने ट्रस की सस्ती लोक लुभावन राजनीति को सिरे से नकार दिया।

लिज़ ट्रस ने अपने पूर्ववर्ती के आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए करों व अन्य छूटों में भारी कटौतियों का वाद किया था। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन उसके परिणाम विध्वंसकारी हुए क्योंकि वित्तीय बाजार धराशाई हो गए और ब्रिटिश पाउण्ड अभूतपूर्ण निचले स्तर पर चला गया।

एक ऐसे देश के लिए जो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए फायनैंशियल सैक्टर पर ही पूर्णतया निर्भर है, वहां महत्व रखने वाले वित्तीय बाजारों की प्रतिक्रिया ने सरकार में भरोसा कम कर दिया। पहले तो उनके वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया और उनकी जगह नया वित्त मंत्री बनाया गया।

नए वित्त मंत्री ने सभी कर छूटों व अन्य बम्बर घोषणाओं को पूर्णतया वापस ले लिया, जिसका मतलब था कि नए वित्त मंत्री प्रधानमंत्री के अधिकार और सत्ता को धता बता रहे थें यह स्पष्ट हो गया था कि लिज़ ट्रस का प्रधानमंत्री पद पर बने रहना अब मुश्किल है। जैसी कि कुछ राजनीतिक टीकाकारों ने टिप्पणी की: लिज़ ट्रस प्रधानमंत्री थीं, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं थी। उन्होंने बढ़ती आलोचनाओं के आगे हथियार डाल दिए और अपना प्रधानमंत्री पद त्याग दिया।

अब सबसे बड़ा प्रश्न यह हैकि क्या फिर से आम चुनाव होंगे या कंज़रवेटिव पार्टी उनकी जगह किसी अन्य नेता को प्रधानमंत्री बनाएगी, लेकिन समस्या ये है कि कंज़रवेटिव पार्टी में गहरा विभाजन है तथा कोई भी एक व्यक्ति पूरी विधायी पार्टी के प्रति निष्ठा का दावा करने की स्थिति में नहीं है।

विपक्षी लेबर पार्टी इस स्थिति को पूरी तरह भुनाने में लगी है। वह अब आम चुनावों की मांग कर रही है ताकि ब्रिटेन की जनता यह निर्णय ले सके कि वह किस तरह से शासित होना चाहती है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- निवर्तमान प्र.मंत्री लिज़ ट्रस, अंतिम प्रधानमंत्री थीं, जिन्हें महारानी एलिजाबेथ ने शपथ दिलायी थी।
- अब ब्रिटेन में क्या मध्यावधि चुनाव होंगे? क्योंकि कंज़रवेटिव पार्टी में एका नहीं है तथा कई खेमों में विभाजित पार्टी अभी सहमत होती नज़र नहीं आती, किसी एक व्यक्ति को प्र.मंत्री बनाने के बारे में।

राहुल असली कर्ताधर्ता

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। राजनैतिक विश्लेषक तथा ए.आई. सी. सी. के पूर्व सचिव पंकज शर्मा का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्टी अध्यक्ष बन जाने के बावजूद, पार्टी को सहज रूप से चलाने का दायित्व राहुल गांधी ही सँभालेंगे।

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया। दरअसल, पार्टी के 137 साल के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- राजनैतिक विश्लेषक व ए.आई.सी.सी. के पूर्व सचिव पंकज शर्मा ने कहा, भले ही खड़गे अध्यक्ष चुने गए हों, पर राहुल ही कांग्रेस के कर्ताधर्ता बने रहेंगे और पार्टी में सभी नियुक्तियां उन्हीं की मर्जी से होंगी।

इन-सर्विस डॉक्टरों को पी.जी. में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा महाराष्ट्र में

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 20 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय पर सहमति की मोहर लगायी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को गुरुवार को खारिज करने से इंकार कर दिया जिसमें स्वास्थ्य और जनकल्याण की सेवाओं में पहले से जुड़े अभ्यर्थियों को वर्ष 2022-23 में महाराष्ट्र के पी.जी. मैडिकल पाठ्यक्रमों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की पुष्टि की गई थी।

जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की एक बैंच ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए टिप्पणी की कि "हाई कोर्ट का आदेश हमारे हस्तक्षेप के दायरे में नहीं आता है।"

बैंच निपुण तिवारी व अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गत 26 सितम्बर के राज्य सरकार के एक प्रस्ताव को चुनौती दी गई थीं। इस प्रस्ताव में महाराष्ट्र में पोस्ट ग्रेजुएट मैडिकल प्रवेश में इन सर्विस अभ्यर्थियों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने निवेदन किया कि प्रवेश प्रक्रिया शुरु होने के बाद प्रस्ताव जारी किया गया जो सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का उल्लंघन है। उस निर्णय में कहा गया था कि प्रवेश प्रक्रिया शुरु होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि 20 प्रतिशत आरक्षण गैर आनुपातिक है क्योंकि पी.जी. मैडिकल पाठ्यक्रमों की 1416 सीटों में से 286 सीटें इन सर्विस कोटे के लिए उपलब्ध हैं, जबकि सिर्फ 69 जनों ने नीट पी.जी. की परीक्षा दी थी जिसमें से केवल 52 को एडमीशन दिया गया। महाराष्ट्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता एडवोकेट अभय धर्माधिकारी ने एडमीशन नियमों में बीच में किसी प्रकार का बदलाव किए जाने से इंकार किया क्योंकि राज्य सरकार के ब्रोशर में स्पष्ट कहा गया है कि इन सर्विस आरक्षण सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रस्तावों पर निर्भर होगा।

कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि महाराष्ट्र के डिग्री कोर्सेज में वर्ष 2007 तक 30 प्रतिशत तक का इन-सर्विस कोटा का, जिस पर दिनेश सिंह चौहान के केस के बाद आपत्तियां उठी थीं। बाद में एक संविधान बैंच ने पी.जी. पाठ्यक्रमों के लिए इन-सर्विस कोटे का मुद्दा हल किया था। कोर्ट ने 17 अक्टूबर के केन्द्र सरकार के निर्णय पर भी विचार किया। इस निर्णय के तहत नीट पी.जी. के कट ऑफ मार्क्स सभी श्रेणियों में 25 पर्सेन्टाइल तक घटा दिए गए थे क्योंकि इसकी मदद से अतिरिक्त अभ्यर्थी काउन्सैलिंग के अगले राउण्ड्स में भाग लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं।

आंध्र प्रदेश में प्रवेश होते ही 3 किलोमीटर लम्बी भीड़ ने स्वागत किया राहुल का

कांग्रेस खुद अचंभित थी, इस उत्साहपूर्ण "वैलकम" से

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। कांग्रेस पार्टी के लिये आज विशेष रुप से खुशी का अवसर था, जब पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तथा वायनाड सांसद राहुल गांधी कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में प्रवेश करते समय संबंधित क्षेत्र के लोग उनके स्वागत में उमड़ पड़े। गौरतलब है कि जब कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के दो टुकड़े करके, तेलंगाना बना दिया था तो दोनों क्षेत्रों की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया था।

आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती कस्बे अनन्तपुर में, अपने समर्थकों की तीन किमी लम्बी लाइनों को देखकर, कांग्रेस को अपने इस पुराने गढ़ को लेकर निश्चित रूप से कुछ आशाएं जागी होंगी, जहाँ से 2004 तथा 2009- के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस से सर्वाधिक सांसद पहुँचे थे तथा इस क्षेत्र में, कांग्रेस के नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार बनने में अहम् भूमिका निभाई थी।

आंध्र के दो टुकड़े करना कांग्रेस के लिये अब तक की सबसे बड़ी राजनैतिक गलती साबित हुई, क्योंकि इसके कारण वह लोकसभा की उन 30 से अधिक सीटों से हाथ धो बैठीं, जो अब इन दोनों राज्यों के दो क्षेत्रीय दलों के पास जा चुकी है- तेलंगाना राष्ट्र समिति तथा जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता वाली वाई.एस.आर.सी.पी.। पिता, वाई.एस. आर.रेड्डी की गांधी परिवार में अटूट आस्था थी तथा उन्होंने अकेले के दम पर राज्य को पार्टी को सौंप दिया था।

लेकिन आज, कहानी पूरी तरह भिन्न हो चुकी है। कांग्रेस इन दोनों राज्यों में थोड़ा-बहुत पाने के लिये जी तोड़ कोशिश कर रही है। इन राज्यों में उसके विधायकों की संख्या भी कुछ खास नहीं है। वस्तुतः आंध्र से तो कांग्रेस का पूरी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- जैसा कि विदित ही है, आंध्र का विभाजन कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी तथा विभाजित आंध्र में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस का सफाया कर दिया था।
- पर, इस जोश भरे स्वागत को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि, इन तेलुगू भाषी राज्यों में कांग्रेस की पुरानी जड़ें जीवित हैं।
- राहुल गांधी ने भी इस अवसर पर काफी सटीक बातें कहीं, जैसे कांग्रेस अगर वापस आयी तो, वो सभी वादे पूरे करेगी, जो आंध्र को विभाजित करते समय जनता से किये थे तथा केन्द्रीय सरकार ने पूरे नहीं किये।
- पर, यूथ व किसान की भारी भीड़ क्या रंग लाएगी चुनाव में, यह पूर्ण विश्वास से अभी नहीं कहा जा सकता।